जाच केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा "रा" द्वारा करवाई गई है जिससे भयंकर भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने, वर्ष 1985 के दौरान सरकारी कार्य करने में अनियमितताओं और घोर कदाचार के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़कर निगमों के अध्यक्षों और महाप्रबन्धकों के खिलाफ पूछ-ताछ/जांच के लिए 6 मामले अपने हाथ में लिए थे । एक भूतपूर्व महाप्रबन्धक के खिलाफ एक मामले में संबंधित विभाग को भारी शास्ति के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। अन्य 5 मामलों की पूछ ताछ/जांच की जा रही है ।

अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध ने प्रश्न में उल्लिखित किस्म की कोई जांच नहीं की ।

संबंधित व्यक्तियों के नाम प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

बिहार को दिया गया अनुदान तथा ऋण

238. **श्री हुक्म देव नारायण यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में बिहार को कितना अनुदान और कर्ज दिया गया है;

(ख) बिहार की कौन-कौन सी योजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं ; और

(ग) उपर्युक्त योजनाएं कब से लंबित पड़ी हैं ?

योजना मंत्रालय में और खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

Allocation of Funds for Urban Development

239. SHRI V. NARAYANASAMY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the allocation of funds in the Seventh Five-Year Plan for the urban development is only 5 per cent of the total demand made by the concerned Department ;

(b) whether Government propose to increase the outlay for urban development ; and

(c) if so, what quantum of the amount is proposed to be allocated ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI AJIT PANJA) : (a) The Ministry of Urban Development sought a provision of Rs. 2236 crores for the Urban Development Programme in the Central Sector for the Seventh Five Year Plan. Keeping in view the resources position, priorities adopted for the Seventh Plan and the allocation made in the Sixth Plan, an outlay of Rs. 168.01 crores was provided. This represents 7.5 per cent of the provision sought by the Ministry of Urban Development. The allocation of Rs. 168.01 crores made for the Seventh Plan marks a step up of 52.7 per cent over the Sixth Plan outlay of Rs. 110 crores.

(b) and (c) As all the resources available for the Seventh Plan have already been allocated among different Sectors, there is no possibility of increasing the allocation for Urban Development.

Indian Scientists working abroad

240. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item